

प्रेषक,

एन० रविशंकर,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक ०३ नवम्बर, 2014

विषय:- उत्तराखण्ड कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न मांगों के लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने के कारण जनसामान्य को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर जनहित याचिका संख्या 167/2014 तथा जनहित याचिका संख्या 166/2014 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2014 को निम्नवत: आदेश पारित किये गये हैं:-

"State Government should take strike of the Ministerial staff very seriously. We request the Chief Secretary to take appropriate action against the striking staff. We also request that unless and until the striking staff return to their work, no salary shall be paid to them. Payment of salary shall be considered only after the striking staff calls off their strike. We also direct the State Government to consider for alternative arrangement. In case strike is not called off, the State Government is requested to consider invoking provisions of Uttar Pradesh Essential Service Maintenance Act, 1966 as applicable to the State of Uttarakhand."

2- मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में शासन द्वारा "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त को लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गये हैं:-

- (1) "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के अनुरूप हड़ताल/कार्य बहिष्कार पर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाए। हड़ताली कर्मचारियों का विवरण आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कोषागार को उपलब्ध कराया जाएगा तथा कोषागार द्वारा तदनुसार हड़ताल/कार्य बहिष्कार पर रहने वाले कर्मचारी का हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि के वेतन का भुगतान न किया जाए।
- (2) जिन सेवाओं में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधान प्रभावी हैं, वहां उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

- (3) हड़ताल/कार्य बहिष्कार के दौरान कार्यालयों में तालाबन्दी करने वाले एवं तालाबन्दी के लिए प्रेरित करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के प्राविधानों के अधीन अविलम्ब कार्यवाही की जाय।
- (4) हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि को बाद में किसी भी दशा में उपार्जित अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश के रूप में अगणित नहीं किया जाएगा बल्कि इस अवधि का सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सेवा में व्यवधान माना जाएगा।
- (5) हड़ताल/कार्य बहिष्कार की अवधि में जो कर्मचारी कार्य पर आते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
- (6) हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कर्मचारी को सामान्य रूप से अवकाश स्वीकृत न किया जाए।
- (7) प्रत्येक विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारी की उपस्थिति की कड़ाई से जांच की जाए और यदि कोई कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें भी हड़ताल/कार्य बहिष्कार में सम्मिलित माना जाए एवं उनके सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय।
- (8) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/जिलाधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता की दशा में उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी।


कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
N. Ravi Shankar .
(एन० रविशंकर)
मुख्य सचिव।

संख्या: 161/जी(1)/XXX(2)/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड
- 2- अधिशासी निदेशक, एन०आइ०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी०एम०एस० बिष्ट)
सचिव।